DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI ▸ 10 जून, 2023 ▸ ----------------------------DATED----------------

भाजपा ने झुग्गीवासियों को फिर दिया धोखाः आप

कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद डीडीए का अवैध विध्वंस अभियान जारीः आप

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आम आदमी पार्टी ने पुनर्वास के नाम पर लाखों दिल्लीवासियों को **बेघर** करने की भाजपा की कुत्सित साजिश की कड़ी निंदा की है। पिछले कुछ महीनों के दौरान, बीजेपी नियंत्रित डीडीए दक्षिण दिल्ली क्षेत्र की बस्तियों में एक अवैध विध्वंस अभियान चला रहा है। इससे पहले, एमसीडी चुनाव से ठीक पहले, डीडीए ने खराब मौसम में हजारों निवासियों को बिना छत के छोड़ दिया था। तब से, आम आदमी पार्टी अवैध और अनुचित विध्वंस अभियान का कड़ा विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की झुग्गीवासियों को फिर धोखा दिया है। अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद डीडीए का अवैध विध्वंस अभियान जारी है। आप का कहना है कि पार्टी की ओर से दिल्ली की कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक आतिशी लगातार वहां के निवासियों के साथ मिल रही हैं और

मौके पर पहुंच कर लोगों से बातचीत करतीं आतिशी।

कालका जी में 3,024 परिवारों में से सिर्फ 1,864 को डीडीए ने दिए हैं फ्लैटः आप

उनके मुद्दों का समर्थन कर रही हैं। पार्टी ने बताया कि हाल ही में अधिवक्ता वंदना सिन्हा ने निवासियों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।

नतीजतन, हाई कोर्ट ने डीडीए को नोटिस जारी किया और विध्वंस अभियान के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीडीए पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए अपना विध्वंस अभियान जारी रखे हुए है। डीडीए निवासियों को बलपूर्वक बेदखल करने और उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति काटने तक चला गया है। मामले की जानकारी देते हुए वकील वंदना सिन्हा ने कहा कि डीडीए कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है। डीडीए को जेजे पुनर्वास नीति 2015 के माध्यम से पीएम आवास योजना के तहत इन निवासियों का पुनर्वास करना था। क्षेत्र में लगभग 3,024 घर हैं, लेकिन केवल 1,864 निवासियों को डीडीए द्वारा पुनर्वास के लिए पात्र घोषित किया गया था। वंदना सिन्हा ने कहा कि इससे 1,029 परिवार बेघर हो गए, हालांकि, एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर से निवासियों को धोखा दिया। चुनाव से ठीक पहले, इन मासूम नागरिकों ने जहां नए घरों की चाबियां दिखाई, जहां झुग्गी वहां मकान देने का वादा किया। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी जानबूझकर जनता को झूठ बोला कि सभी 3024 परिवारों को स्थायी आवास दिया गया है जबकि केवल 1864 को दिया गया है। हमारे पास इन दावों में दर्ज आरटीआई की एक प्रति है और यह स्पष्ट करता है कि केवल 1,864 परिवारों को ही आवास दिया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि सभी निवासियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले अंधाधुंध तरीके से उचित पक्के आवास आवंटित किए जाएं।

नई दिल्ली। सोमवार • 12 जून • 2023

राष्ट्रीय सहारा

पर्यावरण जागरूकता अभियान

नई दिल्ली (वि.)। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकारियों, स्कूली छात्रों, स्थानीय समुदाय और विशेषज्ञों की बड़े पैमाने पर भागीदारी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' रखी गई थी। इस मौके पर प्राधिकरण ने इसी थीम पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस मौके पर एक साथ तेरह विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही यमुना के पश्चिमी तट पर रेलवे के पुराने ब्रिज से आईटीओ बैराज तक फैले यमुना के किनारे के मैदानों पर डीडीए की 200 हेक्टेयर की परियोजना 'यमुना वाटिका में 'यमुना तीरे' कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध और उत्कृष्ट तरीके से आगे के काम पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से पर्यावरण और धरती को होने वाले नुकसान से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खासकर यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह नदी दिल्ली की शान है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और डीडीए के सदस्य विजेंदर गुप्ता और ओपी शर्मा भी उपस्थित थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला शनिवार, 10 जून 2023

विदेश मंत्री ने देश के विकास में युवाओं से मांगा सहयोग

भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान के तहत युवाओं, डॉक्टरों से किया संवाद

अमर उजाला ब्यूरो

जयशंकर ने डॉक्टरों संग की चाय पर चर्चा

केंद्रीय मंत्री डीडीए मुख्यालय विकास सदन में कर्मियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं, उन्होंने सर्वोदय एन्क्लेव में प्रसिद्ध हार्ट सर्जन डा. विवेक कुमार के नेतृत्व में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में प्रसिद्ध डॉक्टरों से मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा चिकित्सक केवल रोगी से ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार से जुड़ जाता है। उन्होंने जनपथ पर आर्ट आफ लिविंग संस्था के सदस्यों से संवाद किया और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी सभी तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की नौ वर्ष की उपलब्धियों पर जनमानस से चर्चा करने व आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत शुरू किए गए संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युवाओं, डॉक्टरों, सरकारी कर्मियों एवं सामाजिक संस्थाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक विकास व राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए युवाओं से सहयोग मांगा। उन्होंने दावा किया कि नया संसद भवन एवं पुनर्विकसित प्रगति मैदान प्रधानमंत्री की समयबद्ध विकास की इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं।

केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने डीयू के रामलाल आनंद एवं आर्य भट्ट कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को जी-20 शिखर सम्मेलन भारत में करने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सामने विकसित भारत को पेश करने का मौका है। जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। इसलिए हमें देश को डिजिटल बनाना होगा, स्किल इंडिया का विकास करना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा।

सिद्धि विनायक के लिए दर्शन : केंद्रीय मंत्री देर शाम सरोजनी नगर के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों से आए प्रवासियों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली में बसे दक्षिण भारतीय समाज के लोगों से कहा कि वह मोदी सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख अपने गृह प्रदेश जाने पर जरूर करें। उनके साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केन्द्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, विधायक संजीव चौरसिया आदि उपस्थित थे।

स्कूलों के अपग्रेडेशन का अधिकार सरकार, सीबीएसई को : हाईकोर्ट

अदालत ने डीडीए की अपील को किया खारिज

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक के स्कूलों का अपग्रेड न तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का डोमेन है और न ही अधिकार क्षेत्र। हाईकोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे दिल्ली सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा किया जाना है।

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 के अनुसार फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) क्षेत्र में वृद्धि के लिए डीडीए की जमीन पर निजी स्कूलों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला डीडीए द्वारा स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाने वाले पहले के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील पर आया है।

न्यायमूर्ति नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने अपने 26 मई को एक फैसले में कहा कि चूंकि स्कूलों को आवंटित भूमि पर एमपीडी-2021 के अनुसार एफएआर में वृद्धि की अनुमति दी गई है, इसलिए कोई उन्नयन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि भूमि पहले से ही आवंटित है और केवल अतिरिक्त एफएआर का ही उपयोग किया जाना है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEW नई दिल्ली। शनिवार ● 10 जून ● 2023 राष्ट्रीय सहारा

भारत पर झलकता है डीडीए के कार्यों का प्रभाव : जयशंकर

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) खास जिम्मेदारी निभा रहा है और उसके कार्यों के कारण न केवल राष्ट्रीय राजधानी में बदलाव आ रहे हैं बल्कि इसका भारत पर प्रभाव भी झलकता है। डीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करते हुए जयशंकर ने कहा कि राजधानी में इसके कारण आने वाला बदलाव देश के शेष भाग पर भी प्रभाव डालता है।

■ विदेश मंत्री ने डीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया संवाद

विदेश मंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज और मैं इस बात पर चर्चा करते थे कि हमारा मंत्री-सचिव का संयोजन सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि हमने कई महत्वपूर्ण दायित्वों को साथ निभाया। डीडीए बेहद खास जिम्मेदारी निभा रहा है और उसके कार्यों के कारण न केवल राष्ट्रीय राजधानी में बदलाव आ रहे हैं बल्कि इसका भारत पर भी प्रभाव झलकता है। उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता भी डीडीए फ्लैट में रहते थे। मैं आप सभी को आपके कार्यों के लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहता था। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थीं। विदेश मंत्री मोदी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर भाजपा के संपर्क अभियान के तहत बैठक और कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
II I SATURDAY I JUNE 10, 2023

DDA carries very special responsibility: Jaishankar

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

External Affairs Minister S Jaishankar during 'Dialogue with Students' event at the Aryabhatta College of Delhi University, in New Delhi on Friday

Ranjan Dimri I Pioneer

External Affairs Minister S Jaishankar said on Friday, the Delhi Development Authority (DDA) carries a very special responsibility and the change they bring is not just for the Capital city, it is an impression of India. He also thanked it as his parents also lived in a DDA flat.

Interacting with the officers and employees of DDA, Jaishankar said any change that is brought in Delhi, also has a model impact on the rest of the country.

"Sushma Swaraj and I used to discuss that our Minister-Secretary combination was the best one as we have carried out many important responsibilities together. DDA carries a very special responsibility, the change that they bring is not just for the capital city, it is an impression of India. Any change brought in Delhi, also has a model impact on the rest of the country and today, the world is looking at us with a great deal of respect," he said. "My parents also lived in DDA flats. I always wanted to thank all of you for the work that you have done," he added.

"I have seen governments over the past 40 years, and this government is completely different. It has a sense of commitment and a sense of responsibility," he said. Minister of State for External Affairs Meenakshi Lekhi was also a part of the event. The external affairs minister has been holding meetings and events as part of BJP's outreach campaign on nine years of the Modi government. Jaishankar, along with former Gujarat chief minister Vijay Rupani, has been deputed by the BJP to oversee a month-long campaign across seven Lok Sabha constituencies of Delhi to highlight the achievements of Narendra Modi Government in its nine years at Centre.

millenniumpost
NEW DELHI | SATURDAY, 10 JUNE, 2023

AAP expresses concern over ongoing demolition drive in South Delhi

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Aam Aadmi Party (AAP) expressed concern over the ongoing illegal demolition drive conducted by the Delhi Development Authority (DDA) in South Delhi, despite a stay order issued by the Delhi High Court.

The demolition drive has resulted in the displacement of numerous slum dwellers in the region. Advocate Vandana Sinha filed a writ petition on behalf of the affected residents, leading to the issuance of a notice by the High Court and an order to halt the demolition drive. However, the DDA has continued with the demolitions, going so far as to forcibly evict residents and disconnect essential services like electricity and water.

According to Sinha, the DDA was entrusted with rehabilitating the residents under the PM Awas Yojana and the JJ Rehabilitation Policy 2015. Out of approximately 3,024 houses in the area, only 1,864 residents were declared eligible for rehabilitation by the DDA, leaving 1,029 families without proper housing.

Prior to the MCD election, the BJP made promises of "Jahan Jhuggi Wahan Makaan" which it did not fulfil. BJP MP Ramesh Bidhuri, during the election campaign, stated that all 3,024 families had been provided with permanent housing. However, an RTI inquiry has revealed that only 1,864 families have received such allocations, contradicting the claims made. The AAP has called for a fair resolution to the issue, urging the DDA to allocate proper permanent housing to all affected families, without discrimination.

DDA'S WORK GIVES IMPRESSION OF INDIA: EAM S JAISHANKAR

NEW DELHI: The Delhi Development Authority carries a very special responsibility and the change they bring is not just for the national Capital, it is an impression of India, External Affairs Minister S Jaishankar said on Friday.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI
DATED 11 जून, 2023 ▸ रविवार

यमुना सफाईः दिल्ली सरकार व एलजी में ठनी

यमुना की सफाई के लिए कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो एलजी बताएंः सौरभ भारद्वाज

हमारे काम का श्रेय लेने के लिए एलजी के प्रयास निराधार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): यमुना सफाई को लेकर दिल्ली के जलमंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर एलजी वीके सक्सेना से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों का श्रेय लेने से पहले एलजी ये बताएं कि क्या उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है? अगर उनके स्तर पर यमुना को साफ करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तो दिल्ली की जनता को बताएं। जलमंत्री ने कहा कि यमुना की सफाई कार्य को लेकर सीएम केजरीवाल शुरू से ही बेहद गंभीर हैं। इसी गंभीरता के चलते ही सीएम ने नवंबर 2021 में यमुना की सफाई को लेकर छह सूत्रीय एक्शन प्लान की घोषणा की और प्लान के मुताबिक काम चल रहा है। ये एक्शन प्लान यमुना को दूषित करने वाले प्रमुख कारकों के समाधान को लेकर बनाए गए हैं, जो सरकार की चल रही पहलों के लिए नींव का काम कर रहे हैं।

सौरभ भारद्वाज

भारद्वाज ने एलजी कार्यालय द्वारा किए गए दावों को निराधार और भ्रामक बताया है और उनकी आलोचना करते हुए कहा कि एलजी के पास दिल्ली जलबोर्ड या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसी) में किसी भी परियोजना को मंजूरी देने का वित्तीय अधिकार नहीं है। उनके द्वारा जलबोर्ड और आईएफसी जैसे विभागों के साथ बैठक कर कार्यों को पूरी तरह से अपनी उपलब्धियां दिखाने के प्रयास किए जा रहे है। जोकि पूरी तरह से भ्रामक और दिल्ली के लोगों के सामूहिक प्रयासों का अपमान है। जलमंत्री ने एलजी से आग्रह करते हुए कहा कि वे हमारे कामों का क्रेडिट लेना बंद करें और सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा की गई व्यापक पहलों में सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित करें। भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल एक आईआईटी इंजीनियर हैं, उनके नेतृत्व में जलबोर्ड ने यमुना में प्रदूषण की समस्या को दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि एलजी कार्यालय निर्वाचित सरकार सीएम केजरीवाल द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को कम करने का प्रयास कर रहा है। जलमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से अंतर्विभागीय समस्याओं को हल करने के लिए हर 15 दिन समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एलजी कार्यालय दिल्ली सरकार द्वारा की गई पहलों को गलत तरीके से पेश कर रहा है।

फाइल फोटो

दिल्ली सरकार बताए आठ साल में यमुना सफाई के लिए क्या काम कियाः राजनिवास

काम किया होता तो एनजीटी दिल्ली सरकार को फटकार नहीं लगाता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): यमुना सफाई के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की बयानबाजी को लेकर राजनिवास ने प्रतिक्रिया दी है। राजनिवास के अधिकारी ने बताया कि मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा जारी किया गया बयान हास्यास्पद, जन-विरोधी व दिल्ली-विरोधी है। यमुना सफाई के नाम पर बैनर फहराने के अलावा यदि इस इस संबंध में दिल्ली सरकार ने पिछले आठ सालों में एक भी ठोस काम किया होता तो एनजीटी इस मोर्चे पर निष्क्रियता के लिए दिल्ली सरकार को फटकार नहीं लगाता और एलजी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं करता। अधिकारी ने 09 जनवरी 2023 के एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि एनजीटी बेंच ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और इस ट्रिब्यूनल के आदेशों के उल्लंघन की स्थिति काफी हद तक असंतोषजनक बनी हुई है, यमुना सफाई की जमीनी स्थिति में सुधार दिखाई नहीं दे रहा है।

वीके सक्सेना

इसीलिए सबसे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी के साथ प्रभावी निष्पादन शासन की जरूरत प्रतीत होती है। ऐसे में उपरोक्त चर्चा के आलोक में हम दिल्ली में संबंधित प्राधिकरणों की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन करते हैं क्योंकि अन्य नदी बेसिन राज्यों की तुलना में यमुना का प्रदूषण अधिक (लगभग 75%) है। ऐसे में हम दिल्ली के एलजी जो संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत डीडीए के अध्यक्ष और दिल्ली के प्रशासक भी हैं। हम उनसे समिति का नेतृत्व करने का अनुरोध करते हैं। साथ ही एनजीटी ने कहा कि 194.5 एमजीडी के अंतर के साथ 573.5 एमजीडी का ट्रीट करने वाले 35 एसटीपी के साथ सीवेज के उत्पादन और उपचार में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। सभी एसटीपी की समय-सीमा (कोरोनेशन पिलर को छोड़कर, जिसे मार्च, 2022 में जून, 2020 की समय-सीमा के विरुद्ध चालू किया गया था) को लगातार बढ़ाया गया है और वर्तमान में इसे 23 जून तक बढ़ाया गया है।

राजनिवास ने कहा कि भारद्वाज को यमुना सफाई के मुद्दे पर बयानबाजी से बचना चाहिए खासकर ऐसे समय में जब उनकी सरकार की ओर से आठ साल की निष्क्रियता के बाद, यमुना और दिल्ली के लोगों के लिए चीजें बेहतर दिखने लगी थीं।

गंदे पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन साल तक लंबी जद्दोजहद के बाद छतरपुर इलाके के असोला फतेहपुर गांव में गंदे पड़े पार्क के सौंदर्यीकरण के शुरुआत की घोषणा कर दी है। इसके लिए 2019 से इलाके के आरडब्लूए व स्थानीय लोगों ने गंदे तालाब के सौंदर्यीकरण का अभियान चलाया था। आरडब्ल्यूए के प्रधान व स्थानीय निवासी ऋषिपाल महाशय की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। उन्होंने कहा कि वे 2019 में भी सासद रमेश बिधूड़ी को डीडीए और डीएम के साथ यहां बुलाकर असोला के जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े ऐतिहासिक तालाब के सौंदर्यीकरण के बाबत ध्यान आकृष्ट कराया था और तभी से इसका प्रयास किया जा रहा था। अब 11 जून को सासद रमेश बिधूड़ी स्थानीय लोगों व ऋषिपाल महाशय की मौजूदगी में इसका उद्घाटन करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च 2021 को इस गांव को शहरीकृत गांव के रूप में मान्यता दे दी और यह पूरा इलाका डीडीए के अंदर चला गया। तभी 24 नवंबर 2021 को डीएम दक्षिणी जिला, डीडीए के अधिकारी और सांसद रमेश बिधूड़ी ने ऋषिपाल की अगुवाई में बुलाई एक बैठक में यह तय किया था कि बहुत जल्द इस गंदे तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों की मंशा पूरी हो रही है। अब इस पार्क में झूले लगेंगे, बुजुर्गों के लिए हरी घास और युवाओं के लिए जिम का निर्माण होगा और इलाके के एक लाख से ज्यादा लोग इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER अमर उजाला नई दिल्ली | रविवार, 11 जून 2023

दस दिन में मानसून देगा दस्तक नालों की नहीं हो पाई सफाई

80% नालों की सफाई का दावा कर रहीं एजेंसियां, पर हकीकत बिल्कुल विपरीत

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मानसून अगले दस दिन में दस्तक देगा, लेकिन नालों की सफाई का काम अभी अधूरा है। सिविक एजेंसियां 80% तक अपने नालों की सफाई होने का दावा कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बड़े नाले प्लास्टिक से भरे हैं। प्रगति मैदान के पास स्थित नाला जो कि सीधा यमुना में गिरता है, इसकी सफाई नहीं हुई है। सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास नाला गंदगी से पटा पड़ा है। दक्षिणी दिल्ली में सागरपुर नाले की हालत खराब है। ऐसा लगता है कि इसकी सालों से सफाई नहीं हुई। इसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग व डीडीए के कई नाले हैं, जिनकी सफाई होनी बाकी है।

दिल्ली में हर साल मानसून आने से पहले 15 जून तक नालों की सफाई का काम पूरा करना होता है। इस साल नालों की सफाई का काम देरी से शुरू हुआ। एमसीडी ने फिलवक्त अपने नालों की सफाई के लिए 30 जेसीबी लोडर, 35 बैकहो लोडर, 25 स्कीड सिटयर लोडर, सिल्ट इत्यादि की ढुलाई के लिए 196 टाटा ट्रक, 63 टाटा-909 ट्रक, 36 टिप्पर-407 लगाए गए हैं।

निगम के एक्शन प्लान के मुताबिक मौजूदा समय अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चार फुट से चौड़े 453 किमी लंबाई में नालों की सफाई का काम जारी है। करीब 55% सफाई का काम अभी तक किया गया है। चार फुट से कम चौड़े 20884 नालों की सफाई का काम पर्यावरण विभागों द्वारा किया जा रहा है। इन नालों की कुल लंबाई 6657 किमी है। इनकी सफाई का काम करीब 72% हुआ है।

12 जोनल कंट्रोल रूम व केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाए : जलभराव की समस्या से निपटने के लिए निगम ने केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 12 जोनल कंट्रोल रूम बनाए हैं। ये 15 जून से 24 घंटे काम करेंगे। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में टोलफ्री नंबर 155304 व 155305 पर जलभराव की शिकायत की जाएगी। समाधान के लिए यहां से तुरंत पंप, उपकरण व कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

सागरपुर नाला

सराय रोहिल्ला

सफाई कर्मियों का स्क्वायड वार्डों में होगा तैनात

निगम के पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग द्वारा हर एक वार्ड में 8-10 सफाई कर्मियों का एक स्क्वायड तैनात किया जाएगा। ये जलभराव होने पर तुरंत कार्यवाही करेंगे। जलभराव के व्यवधानों जैसे कि बेल माउथ, गली ग्रेटिंग इत्यादि को तुरंत साफ करेंगे। नाले, नालियों, जालियों में फंसे प्लास्टिक, कूड़े, कचरे को निकालेंगे।

480 मोबाइल पंपिंग सेट रहेंगे उपलब्ध

निगम के पास 72 स्थायी पंपिंग स्टेशन हैं, इसके अलावा इस बार 480 मोबाइल पंपिंग सेट्स तैनात रहेंगे। इन सभी को जोनों में आवश्यकता के लिहाज से तैनात किया जाएगा। निगम के मुताबिक सड़कों पर जल भराव न हो इसके लिए पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीडीए, दिल्ली मेट्रो इत्यादि एजेंसियों के साथ इंटर डिपार्टमेंटल बैठक लगातार की जा रही है।

प्रगति मैदान, आईपी डिपो के पास गाद से पटा नाला

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 10 जून 2023 TED

रंग ला रही मेहनत, यमुना और नजफगढ़ नाले के पानी में लगातार हो रहा है सुधार

एलजी वी. के. सक्सेना ने हाई लेवल कमिटी की पांचवीं बैठक में जताई संतुष्टि

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

यमुना की सफाई के लिए बनी हाई लेवल कमिटी के बाद से यमुना और नजफगढ़ नाले के पानी में लगातार सुधार हो रहा है। शाहदरा नाले में बीओडी का स्तर 40 प्रतिशत, आईएसबीटी में 31 प्रतिशत तक कम हुआ है। एक साल के दौरान ही मई 2023 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। नजफगढ़ नाले का बीओडी स्तर 37 प्रतिशत कम हुआ है।

कमिटी की 5वीं बैठक शुक्रवार को हुई

नजफगढ़ नाले का बीओडी स्तर 37% कम हुआ : रिपोर्ट

हाई लेवल कमिटी की पांचवीं बैठक में एलजी वी के सक्सेना ने इस पर संतुष्टि जाहिर की। यमुना से जुड़े 29 में से 17 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। यह प्रोजेक्ट जमीन से जुड़े मसलों की वजह से रुके हुए थे। 17 एसडीपी/डीएसटीपी प्रोजेक्ट्स के लिए डीडीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले महीने जमीन अलॉट कर दी है।

हर महीने की रिपोर्ट में पाया गया कि यमुना और नालों के पानी में बीओडी का स्तर लगातार सुधर रहा है। इस दौरान 29 प्रोजेक्ट्स पर जमीन न मिलने की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। एलजी के दखल के बाद एक महीने में इनमें से 17 प्रोजेक्ट के लिए डीडीए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमीन अलॉट कर दी है। बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट का काम भी जल्द शुरू होने की संभावना है।

यमुना की हाई लेवल कमिटी आठ कामों को आधार बनाकर यमुना की सफाई में जुटी है। इनमें राजधानी का पूरा सीवेज ट्रीट करना, सभी नालों को यमुना में गिरने से पहले रोकना और साफ करना, अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टर में सीवेज नेटवर्क का निर्माण, उद्योगों में सीईटीपी लगाना, सेप्टेज मैनेजमेंट, यमुना बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित करना, ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करना और नजफगढ़ झील के एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान पर काम करना शामिल है।

डीपीसीसी के अनुसार, जनवरी से अब तक नजफगढ़ नाले का बीओडी स्तर 80 एमजी लीटर से कम होकर 53 एमजी लीटर हो गया है। आईएसबीटी पर यमुना में बीओडी का स्तर 55 एमजी प्रति लीटर से कम होकर 38 एमजी आ गया है। शाहदरा ड्रेन में बीओडी 80 एमजी प्रति लीटर से 48 एमजी प्रति लीटर रह गया है।

हाई लेवल कमिटी की मीटिंग पर दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान जारी किया है। सौरभ ने कहा है कि आईआईटी इंजीनियर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में डीजेबी सीधे उन जमीनी मुद्दों पर काम कर रहा है, जिनसे यमुना को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। केजरीवाल द्वारा पहले ही इन समस्याओं को चिह्नित कर 6 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार कर 2021 में मीडिया के साथ शेयर किया जा चुका है। बहुत दुख की बात है कि दिल्ली सरकार की ओर से पिछले कई वर्षों से यमुना की सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का क्रेडिट एलजी साहब खुद ले रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 10 जून 2023 -DATED-

काम के लिए पहले खोदी रोड फिर मिट्टी डालकर छोड़ दी

■ एनबीटी न्यूज, जसोला

जसोला में लोकल एजेंसियों की लापरवाही का खामियाजा लोग भुगत रहे

लोकल एजेंसियों की लापरवाही का खामियाजा जसोला के लोग भुगत रहे हैं। जसोला क्षेत्र की करीब 40 फीसदी सड़कों को लोकल एजेंसियों ने अपने कामों के लिए खोद दिया, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। ऐसे में लोग पिछले एक साल से बुरी तरह से परेशान हैं।

एनबीटी सुरक्षा कवच ग्रुप से जुड़े आरडब्ल्यूए के सचिव बीके पिल्लई ने बताया कि प्राइवेट बिजली कंपनी और दिल्ली जल बोर्ड ने अंडरग्राउंड बिजली की मोटी केबल और सीवर लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की थी। इन्होंने काम पिछले साल शुरू किया था। जसोला मेट्रो स्टेशन से लेकर पॉकिट, 1, 2, 10वीं, 12 और जसोला विलेज की सड़कों को खोद दिया गया था। करीब 6 महीने पहले काम पूरा होने के बाद सड़कों को नए सिरे से बनवाने की जगह इन्हें मिट्टी से भर दिया गया। इसी बीच हुई बारिश ने हालात और भी खराब कर दिए। इससे सड़कों पर बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। सड़क की मिट्टी नीचे की तरफ धंस भी गई है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर निकलना ही एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फुटपाथ भी पूरी तरह से नहीं बने हैं। लोगों ने इस संबंध में डीडीए से संपर्क करके समस्या दूर करने की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने लोगों को बताया है कि लोकल एजेंसियों से बात की जा रही है।

NBT सुरक्षा कवच
मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

रोड की इस हालत से लोग पिछले एक साल से बुरी तरह से परेशान हैं

40% फीसदी सड़कों को लोकल एजेंसियों ने कामों के लिए खोदा था

पिछले दिनों बही मिट्टी, बढ़ी दिक्कत

अक्सर हादसे भी हो रहे हैं

जयशंकर ने DU छात्रों को बताई केंद्र की उपलब्धियां

■ प्रस, नई दिल्ली : केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में छात्रों के बीच पहुंचे। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि मैं डीयू का ही छात्र रहा हूं और मुझे पढ़ाई पूरी किए 50 साल हो गए। उन्होंने छात्रों को केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताईं।

विदेश मंत्री ने छात्रों को जी-20 शिखर सम्मेलन का महत्व समझाया और कहा कि यह सिर्फ सम्मेलन नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने विकसित भारत की छवि पेश करने का अवसर है। इससे विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ेगा। छात्रों को अगर बेहतर एजुकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो देश का विकास अधूरा होगा। नई दिल्ली एरिया में भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की। जयशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सदस्यों से भी बात की और मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करने को कहा। मंत्री ने सरोजिनी नगर के सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किया और दक्षिण भारत से आए प्रवासियों की एक सभा को संबोधित किया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर डीडीए के 75 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में पहुंचे

'दिल्ली से बनती छवि'

भारत की छवि दिल्ली से बनती है। 75 प्रतिशत भारत की छवि दिल्ली के विकास से आंकी जाती है। इसलिए डीडीए जो विकास कार्य दिल्ली में कर रहा है, वह पूरे भारत की छाप है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डीडीए के 75 साल पूरे होने पर विकास सदन में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इस कार्यक्रम में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राजधानी का चेहरा बदलने में डीडीए ने इन 75 सालों में अहम भूमिका निभाई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
NAME OF NEWSPAPER THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, JUNE 10, 2023

Improvement seen in Yamuna, Najafgarh drain water quality as biochemical oxygen demand dips

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 9

WATER QUALITY in Yamuna is showing signs of improvement with the biochemical oxygen demand (BOD) – the proportion of which determines the level of pollution in a water body – in the Najafgarh drain as well as in the river from the point where it meets the drain having fallen compared to last year, according to Delhi Pollution Control Committee (DPCC) figures presented at a meeting on Friday.

During the fifth meeting of the High-Level Committee for rejuvenation of the Yamuna, chaired by Lieutenant Governor V K Saxena, progress on work so far was reviewed. The committee was constituted on the orders of the National Green Tribunal (NGT) in January.

According to a communication from the L-G's office, DPCC data shows that the BOD level in the Najafgarh drain, which was 80 mg/litre in January 2022, had dropped to 53 mg/litre in January 2023. Further, the figure that was 76 mg/litre in May 2022 had dropped to 48 mg/litre in May this year. With several other drains meeting the Najafgarh drain and the latter eventually meeting the Yamuna near Wazirabad, ensuring clean water in the drain is crucial to keeping the river clean.

A BREATHER

Findings shared in meeting on Yamuna rejuvenation

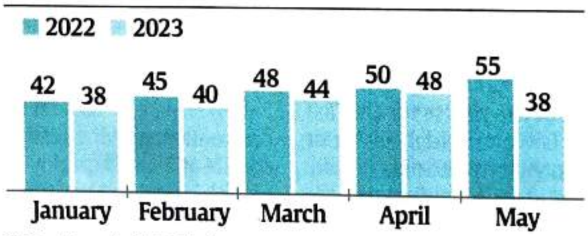

(Data from Delhi Pollution Control Committee with regard to ISBT, Kashmere Gate -- the point after Yamuna river meets Najafgarh drain)

At ISBT Kashmere Gate, a location from where the DPCC draws water for testing after the Najafgarh drain merges into the river, the BOD level, which was 42 mg/litre in January 2022, had fallen to 38 mg/litre in January 2023, according to DPCC data presented at the meeting. In May, the BOD level in the river at ISBT was 55 mg/litre in 2022 and 38 mg/litre in 2023.

A total of 17 projects for sewage treatment plants, out of 29 that were earlier held up due to non-availability of land, have now been allotted land by the Delhi Development Authority (DDA) and the Revenue Department, according to the communication from the L-G's office.

When the NGT issued its order on pollution in the Yamuna in January, it had said that the success of the committee would be viewed in terms of reduction of pollution load, adding the committee's targets should be measurable and identifiable. The tribunal's order had said that a pollution graph should be prepared on a quarterly basis with the goal of "substantial reduction" by July 1.

Rejuvenation of the Yamuna that is being monitored by the committee includes treatment of sewage and associated expansion of the sewerage network along with construction of sewage treatment plants, treatment of industrial effluents, restoration of the floodplains and management of the Najafgarh jheel.

Timelines on work must be met and seamless inter-departmental coordination is to be ensured, Saxena told officers, according to the communication issued by his office after the meeting.

According to the final report of the erstwhile Yamuna Monitoring Committee submitted in 2020, "improvement in the quality of river water is linked to the twin factors of maintaining a minimum flow of fresh water and reduction in the discharge of polluted water, both domestic and industrial, joining the river."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------------------------------DATED-----

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JUNE 10, 2023

Their dream house is rather watered down

Ridhima Gupta & SV Vaishnavi | TNN

Photos: Rajesh Mehta

New Delhi: Sahid Alam moved out of his slum shack at Bhoomiheen Camp in south Delhi in February to a DDA flat allotted to him at Kalkaji Extension under the in situ rehabilitation project. With a proper house in his name, Alam, 39, thought his life would change. It did — but not in the way he thought it would.

Alam was allocated a one BHK flat with a carpet area of 25 sq metres after paying Rs 1.24 lakh, including Rs 30,000 as maintenance charges for the first five years. He now says he wouldn't mind going back to his old life in the slums. The myriad issues he has faced in the new DDA flat have left him deflated. Water supply is a problem, the flats are poorly maintained and many have seepage issues.

In November 2022, Prime Minister Narendra Modi had handed over the keys to the eligible beneficiaries of Bhoomiheen Camp after inaugurating 3,024 flats, constructed at a cost of Rs 345 crore. The bubble burst soon enough when water woes became a headache. At the complex, **TOI** saw water tankers ferrying water to the flats. Several residents claimed this has been the case ever since they shifted there. Bishwajeet Sarkar, 32, who lives in Block B, said, "The storage tanks haven't been cleaned and the water we are given by the tankers is unhygienic."

Sarkar added that when they were allotted their flat a few months ago, the house did not have doorknobs and window panes.

Just as exasperated and waving a copy of his written complaint, Shikant Biswas, 39, who moved into his flat in A Block a month ago, raged, "How can I move into a flat with no door and taps? It's a new flat yet there is water seepage on the kitchen ceiling. Every day, I urge the official to fix these issues only to hear them tell me to return later because they don't have the materials for repairs." With his house in Bhoomiheen Camp demolished, he doesn't have a plan B either.

Just as frustrated is Jharna Mandal, 50, a domestic worker. She has made umpteen complaints about the poor quality of water and the leaking ceiling to no avail. She and others are justifiably aggrieved. Her neighbour fumed, "Why did DDA charge us for maintenance if they cannot do it?"

There were also complaints about non-functional lifts. Niti Dutta, 52, who has paralysis in one of his legs, said, "My flat is on the 14th floor and on most days, the lift does not work. It is very difficult for me to come and go from home. We were excited about a new life in a high-rise, but every day we run into a new problem."

Responding to **TOI's** queries, DDA officials claimed that the water supply was the responsibility of Delhi Jal Board. "DDA is continuously pursuing DJB to provide bulk water meter connection, but the request is pending," said an official. "DJB has also been requested to proportionally divert water from Bhoomiheen Camp to this residential complex with the camp residents having shifted here, but it has not acceded to our request. DDA is currently paying for the water tankers."

The official admitted that sanitary fittings installed prior to the handing over of the flats had been stolen. "We have registered FIRs for these thefts and are in the process of replacing the stolen taps," the official said, while claiming, "All lifts are operating and we are attending to complaints immediately."

According to DDA, 1,862 eligible families from Bhoomiheen Camp were allotted flats at Kalkaji Extension. The remaining 1,162 flats will be allotted to households from the JJ cluster in Govindpuri and Kalkaji after determining their eligibility under the DUSIB policy for resettlement of slum dwellers.

Demolitions of the vacated shacks at Bhoomiheen Camp are under way and 170 of the 262 structures have been brought down. The rest haven't been touched yet due to the stay ordered by Delhi High Court and the acceptance of some appeals by the appellate authority constituted by DDA.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
NAME OF NEWSPAPERS------ नई दिल्ली, 10 जून, 2023 ---------------DATED---------------------

यमुना और नजफगढ़ नाले में बीओडी के स्तर में कमी

एचएलसी की बैठक में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिशों से मिले सुधार के संकेत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में यमुना नदी के कायाकल्प के लिए एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की पांचवीं बैठक शुक्रवार को राजनिवास में हुई। बैठक में यमुना के कायाकल्प को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रगति और हासिल लक्ष्यों पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने एलजी को बताया कि नजफगढ़ नाले की सफाई का काम अगस्त 2022 में शुरू किया गया था। साथ ही जनवरी 2023 में एचएलसी गठन के बाद यमुना की सफाई का काम शुरू किया गया, जिसके बाद से नाले और यमुना के पानी की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है। मई 2022 से मई 2023 के बीच तो नाले व नदी के पानी में बीओडी के स्तर में अपेक्षित सुधार देखा गया है। साल 2022 में फरवरी, मार्च और अप्रैल की तुलना में 2023 की समान अवधि में भी बीओडी में लगातार कमी दर्ज की गई है। इस संबंध में दिए गए प्रजेंटेशन पर एलजी ने संतोष जताते हुए कहा कि विभिन्न हितधारक विभागों के सामूहिक प्रयासों के परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मुश्किलों और भविष्य के कार्यों के प्रति आगाह भी किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रमुखों को तय समय में काम पूरा करने के लिए आपस में मिलने और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने की बात भी दोहराई।

बैठक में यह बात सामने आई कि बेहतर तालमेल की वजह से एसटीपी/डीएसटीपी के निर्माण समेत दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जो भूमि संबंधी मुद्दों के कारण वर्षों से लंबित थीं, को भी अंततः गति मिल सकी है। लंबित मुद्दे भी हल किए जा रहे हैं। भूमि की कमी के कारण वर्षों से अटकीं 29 परियोजनाओं में से 17 को एलजी के हस्तक्षेप के बाद एक महीने के दौरान डीडीए/राजस्व विभाग द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। शेष का समाधान भी जल्द होने वाला है। तय लक्ष्यों के साथ एचएलसी आठ विशिष्ट कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत यमुना के कायाकल्प की निगरानी कर रहा है, जिसके तहत संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्य योजना बनाई और क्रियान्वित की जाती है। इनमें सीवेज का 100 प्रतिशत शोधन, सभी नालों की ट्रेपिंग, अनधिकृत कालोनियों व जेजे क्लस्टर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण, सीईटीपी के जरिये औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन, सेप्टेज प्रबंधन, यमुना बाढ़ क्षेत्र का जीर्णोद्धार और कायाकल्प, उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग व नजफगढ़ झील की पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल है।

>> यमुना नदी की सफाई को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक लेते एलजी वीके सक्सेना • सौ. राजनिवास

- मई 2022 की तुलना में इस वर्ष मई में यमुना में शाहदरा नाले पर बीओडी का स्तर 40 तो आइएसबीटी पर 31% कम हुआ
- उपराज्यपाल ने कहा- अब आने शुरू हो गए हैं विभिन्न हितधारक विभागों के सामूहिक प्रयासों के अपेक्षित परिणाम

नजफगढ़ नाले में बीओडी का स्तर

80% जनवरी 2022 | 53% जनवरी 2023
76% मई 2022 | 48% मई 2023

आइएसबीटी पर यमुना नदी में बीओडी का स्तर

42% जनवरी 2022 | 38% जनवरी 2023
55% मई 2022 | 38% मई 2023

शाहदरा नाले का यमुना नदी में मिलने के बाद बीओडी का स्तर

60% जनवरी 2022 | 56% जनवरी 2023
80% मई 2022 | 48% मई 2023

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED------------------------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JUNE 10, 2023

EAM's Diplomacy Lessons At Summit With Students

Focus On Our Neighbours Now Restored, Says Jaishankar

Shradha.Chettri
@timesgroup.com

New Delhi: Answering a question by a student on what India could have done better in foreign policy in the last nine years, external affairs minister S Jaishankar said India could have remained more focused on working with its neighbours. He added, however, that such a focus was restored and now these countries think India is their biggest friend. He told the student that if he remembered anything besides this, he would tweet it.

Jaishankar was at Delhi University's Aryabhatta College on Friday as part of BJP's outreach programme ahead of the 2024 general elections. Delhi BJP president Virendra Sachdev and New Delhi MP Meenakshi Lekhi were part of the event.

When a student of Ram Lal Anand College asked the question on the foreign policy, Jaishankar said, "It is hard to pinpoint one single decision that could have been better. What happens sometimes is you want to do something but the focus is not where you want it to be." He said that people in the neighbouring countries had fixed ideas about India. "They said nice things about us, but said other things too. In between various problems arose. But we should have kept at it strongly."

Rajesh Mehta

Jaishankar was at Delhi University's Aryabhatta College on Friday as part of BJP's outreach programme ahead of the 2024 general elections

S JAISHANKAR SAYS

The problem is when you ask people from outside to interfere in what is happening here, saying it's a global concern. That I think is not good for the country

However, the minister added that now, whether it was Nepal, Bhutan, Sri Lanka or Bangladesh, all thought of India as a good friend because of the help rendered to them during Covid and economic crises.

Responding to a comment about opposition leaders talking about India and its problems abroad, Jaishankar said, "In any democracy, there will be arguments, differences, diversity and opinions. There should be too, it is important for democracy. But the problem lies when you take it out and ask people from outside to interfere on what is happening here, saying it's a global concern. That I think is not good for the country."

Talking about the nine years of the Modi government, he said, "We are close to the moment when we have to again win the trust of the people. So, we are here to remind you about the work that has taken place in the last nine years." He talked about India's G20 presidency and how the health infrastructure and the digital setup had been boosted even in the most remote parts of the country under Modi.

The minister said that what differentiated Modi from other political leaders and stalwarts outside politics was his faith in the country and its people. "I have been a diplomat for 40 years but I decided to join politics because I wanted to make a change. I got a chance to do so because we have a leader with a vision who is committed to the country," he said.

After meeting the students, Jaishankar visited the DDA headquarter at Vikas Sadan to meet members of the DDA Workers' Association. He lauded them for the work being done by DDA to ease life in the city. He said Delhi, like the rest of India, saw major changes in the last few years because of strong leadership at the Centre.

At Sarvodaya Enclave in south Delhi, he met renowned heart surgeon Dr Viveka Kumar. There he said, "A doctor does not connect only with the patient, but with the patient's entire family. I request all doctors to spread awareness about Ayushman Bharat Yojana for the poor and about Jan Aushadhi Kendras, which provide cheap medicines to everyone."

The minister later interacted with the members of the Art of Living at Janpath, appreciating their work during the pandemic. He ended the day with blessings at Vinayak Temple in Sarojini Nagar.

Vision 2041: Flats for slum dwellers, sustainable development in focus

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: At an interaction with external affairs minister S Jaishankar and his junior minister Meenakshi Lekhi, Delhi Development Authority vice-chairman Subhasish Panda gave updates on the agency's projects on in-situ slum rehabilitation, transit-oriented development, land pooling and the restoration of the Yamuna floodplain, among others.

At the ministers' interaction with DDA workers as part of the national outreach to mark nine years of the Modi government, Panda said, "While the work is in progress at the first TOD in Karkardooma, 12 other TOD nodes have been identified. Given that mixed-use development will help reduce travel time, walking distances and provide a safe environment, we are creating these structures near major multi-modal transit hubs, highways, etc."

There are 10 sites identified for in-situ rehabilitation covering 18 slums. "At present, work has been completed at one in-situ project in Kalkaji," the vice-chairman said. "The project at Jailorwala Bagh is likely to end in August and at Kathputli Colony, by December-end."

Of the 138 sectors identified for land pooling, in 20 sectors, 70% land pooling had been accomplished and consortium formation notice issued in two sectors while provisional notices had been issued in 12 sectors. Panda elaborated, "The land pooling policy is applicable in 105 villages and the total poolable land is 20,640 hectares. Of this, 7,435 hectares have been pooled."

Panda also said that DDA was taking steps to increase the sale of flats, of which it had an inventory of 40,000 units. "Besides amending regulations, such as permitting a person who already owns a DDA flat to apply for another, we are offering flats to people from the lower economic strata at highly subsidised rates, inviting government departments/organisations to buy flats and giving some relief to the general public," he said.

As for the rejuvenation of the Yamuna floodplain, Panda claimed that 90% of the work had been done in four of the 10 restoration sites with the rest to be finished by December. "We faced challenges such as portions of our developed land being taken over for the RRTS and NHAI projects. We will focus on at least rejuvenating the remaining land," said the vice-chairman.

DDA plans to develop about 200kmm of cycle-walk track over five phases. In the first phase, a 36km stretch for both on-grade and elevated tracks has been planned. "The track will go via parks and green areas and not roads, so this will require permissions. We have submitted a plan to the principal committee for approval," said Panda.

He also revealed that work on the Urban Extension Road II project was finished and was due for inauguration. "DDA is also working on a drain rejuvenation project in Dwarka in two places covering areas of 5.3km and 3.8km," said Panda.

WHAT'S IN STORE

SIX OBJECTIVES AND POLICY AREAS

1 Prioritising environment sustainability by encouraging landpooling, green development

2 Facilitating economic development

3 Enhancing heritage, culture and public life; giving incentives to those contributing in conservation

4 Improving housing and social infrastructure, including cycling tracks, housing schemes

5 Moving towards low carbon mobility

6 Developing resilient physical infrastructure and urban regeneration

ACHIEVEMENTS

> 10 sites identified for in situ slum development; DDA is working in coordination with MoHUA to form a policy

> 12 transit-oriented development nodes identified

> Of the 138 sectors identified for landpooling in 20 sectors, 70% under landpooling; consortium formation notice issued in two sectors and provisional notices issued in 12 sectors

> Having 40,000 inventory/unsold flats, DDA offering them to poor people at highly subsidised rates

> 90% work completed at four out of 10 restoration projects on Yamuna floodplain

> These include a 16-hectare site running from Wazirabad to Old Railway Bridge named as Vasudev Ghat by the PM

> DDA plans to develop about 200km of dedicated cycle track divided into five phases

> Phase-I (Approx 36km) plan submitted to the principal committee for approval

> Drain rejuvenation project in Dwarka in two phases spread over 5.3 and 3.8 kilometres is in progress

> Urban Extension Road-II project completed and due for inauguration

> 16 DDA parks desveloped and named after unsung heros

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 10 जून, 2023 दैनिक जागरण

डीडीए जो भी बदलाव लाता है, उसकी छाप पूरे देश पर पड़ती है : एस. जयशंकर

- डीडीए के 75 वर्ष पूरे होने पर इसके अधिकारियों व कर्मियों से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री
- पीएम नरेन्द्र मोदी के विजन से हो रही भारत की प्रगति को बताया उल्लेखनीय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बहुत खास दायित्व वहन करता है। डीडीए जो बदलाव लाता है, उसकी छाप दिल्ली ही नहीं है बल्कि पूरे भारत पर पड़ती है। डीडीए के 75 वर्ष पूरे होने पर विकास सदन में आयोजित कार्यक्रम में जयशंकर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली में जो भी बदलाव होता है, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी के विजन से हो रही भारत की प्रगति को उल्लेखनीय बताया और कहा कि वे देश ही नहीं वैश्विक बेहतरी की भी महत्वाकांक्षा रखते हैं।

विदेश मंत्री ने अतीत की यादें ताजा करते हुए कहा, सुषमा स्वराज और मैं चर्चा करते थे कि हमारा मंत्री-सचिव संयोजन सबसे अच्छा था, क्योंकि हमने एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। आज दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देख रही है। उन्होंने कहा, 'मेरे माता-पिता भी डीडीए के फ्लैट में रहते थे। मैं हमेशा आप सभी को आपके द्वारा किए गए काम के लिए धन्यवाद देना चाहता था।'

कार्यक्रम में संस्कृति एवं विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल हुईं। उन्होंने अपने वक्तव्य में राजधानी का चेहरा बदलने और इसे विकास के पथ पर अग्रसर करने के डीडीए के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। यमुना के आसपास जैव विविधता पार्क और यमुना बाढ़ के क्षेत्रों को फिर से बेहतर बनाने, प्रवासी पक्षियों की 55 प्रजातियों को संरक्षित करने जैसे विभिन्न प्रयासों के लिए डीडीए की सराहना की। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नौ साल में तो भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा खोदे गए गड्ढे ही भरे हैं, इमारत बनाना अभी बाकी है।

कार्यक्रम के दौरान डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा ने एक प्रजेंटेशन देकर डीडीए के 75 साल लंबे सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह डीडीए दिल्ली वालों के जीवन में बदलाव लाया और समय-समय पर हर क्षेत्र में कितनी योजनाएं लेकर आया। पांडा ने यह भी कहा कि डीडीए अध्यक्ष एवं एलजी वीके सक्सेना के मार्गदर्शन व नेतृत्व में आने वाले कुछ ही समय में दिल्ली का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा।

विकास सदन मे कार्यक्रम को संबोधित करतीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। मंच पर हैं विदेश मंत्री एस. जयशंकर, डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा एवं अन्य • सौ. डीडीए

Hindustan Times
NEW DELHI
SATURDAY
JUNE 10, 2023

DDA to build new ghat on Yamuna, 200km cycle track

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

200km
Long continuous network of cycle tracks

₹500crore
Project cost

According to officials, the cycle tracks will be developed in three phases, and some of them will pass through various parks and green areas

NEW DELHI: In an initiative aimed at building continuous non-motorised infrastructure in the city, the Delhi Development Authority (DDA) will develop over 200km of cycle tracks across the Capital at the cost of ₹550 crore, officials said on Friday. The tracks will be developed in three phases, and some of them will pass through various parks and green areas, the officials said.

"We have already sent the proposal for the entire network to the Supreme Court's principle committee for green areas for approval. We are hoping that the first phase of 36km will be approved soon," said Subhasish Panda, DDA vice-chairperson.

While an initiative to promote non-motorised transport in a traffic-choked city is welcome, haphazard development of cycle tracks will not be helpful. Delhi already has several kilometres of cycle tracks but these lie unused because of encroachment, misuse and lack of practical routes. To ensure safety of cyclists and encourage such transport, the authorities will need to focus on holistic development of safe cycle tracks that are seamless and practical. So far these initiatives have not worked despite elaborate plans.

The announcement came at a press conference organised by DDA to apprise Union external affairs minister S Jaishankar and minister of state (MoS) Meenakshi Lekhi about its ongoing work and the achievements. Jaishankar is the Delhi in-charge of the BJP's 30-day campaign, which started on Thursday, to highlight the party's achievement over the last nine years.

In another announcement, Panda said that DDA is developing a new ghat on the western bank of Yamuna, which will be called Vasudev Ghat on Prime Minister Narendra Modi's suggestion, where at least 1,700 native trees will be planted.

DDA said the Project Sanctioning Committee under Urban Development Fund of the Union ministry of housing cycle tracks project has given its nod to the cycle tracks project. While 80% of the cost will be borne by UDF, DDA will incur the remaining cost. Officials said that the plan includes 2.5-metre-wide cycle tracks and two-metre-wide pedestrian tracks.

"The tracks will have origin and destination plazas, intermediate stations, land bridges and other ancillary development work such as plantation," said a DDA official, asking not to be named. The tracks were largely planned in the NDMC areas.

According to experts, the tracks need to be segregated and continuous for these to be used by regular commuters. "...Why these are easily encroached upon is because these are not built properly and are not even preferred by cyclists. Cycle tracks have to be completely accessible and segregated from high-speed traffic, so that cyclists are safe," said Sarika Panda Bhatt, co-founder, Raahgiri Foundation.

On the upcoming Yamuna ghat, the DDA VC said it will be built between the existing Yamuna ghat and Nigam Bodh Ghat. Spread over 16 hectares, DDA said it has started cleaning the area and planting of saplings.

"Wastewater from the existing drains will be filtered using coir logs and reed plantation before releasing into the river," said the official cited above.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER Hindustan Times
NEW DELHI
SUNDAY
JUNE 11, 2023

Five sports facilities in Dwarka, Rohini by Dec

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: Five of the six new sports complexes in Dwarka and Rohini will be open to the public by end of this year, the Delhi Development Authority has said, in what is touted as a major push to growth in the largely residential areas of the city.

Another key project, an 18-hole golf course in Dwarka Sector 24 spread across 166 acre — the largest golf course in the city built by DDA, is also scheduled to be thrown open by year-end, according to officials aware of the matter. It is being built at a total cost ₹152.47 crore, the officials added.

The soon-to-open sports complexes include one in Dwarka Sector 17 being built at a cost of ₹92 crore; the project was earlier scheduled to finish by July this year, officials said.

Meanwhile, the construction work for sports complexes in Sectors 23, 8 and 19 in Dwarka and Sector 33 in Rohini is underway, officials said.

"All of these five sports complexes as well as the golf course are about to be completed and will be opened by the end of this year. Most of the infrastructure development work is done and we are working on the final touches. Once that is done, tenders will be floated for coaches and maintaining other facilities," said Subhasish Panda, Vice chancellor, DDA.

The facility in Dwarka Sector 8 will be the largest among the five new projects. Spread across 23.3 acre, it is being built at a cost of ₹66.75 crore, and will be developed as a centre of excellence in wrestling, weightlifting, boxing, judo and kabaddi.

The sports complex in Dwarka Sector 23 is spread across 17.5 acre and is being built at a cost of ₹39.67 crore. It will developed as a centre of excellence in football and hockey.

The 19.9 acre Dwarka Sector 19 sports complex is being constructed at a cost of ₹81.79 crore as a centre of excellence in tennis and shooting, while the Rohini sports complex in Sector 33 has an area of 22.82 acre and is being constructed at a cost of ₹109.51 crore. With an Olympic-size swimming pool, it will be a centre of excellence in aquatics, according to DDA.

The land owning authority has also started work on one of the Capital's largest integrated sports complexes in Dwarka Sector 19B, which will have a 30,000-seat cricket-and-football stadium, apart from an indoor multi-sports facility.

Spread over 53 acre, it will be DDA's the first sports project to be developed on a public-private partnership. It will also have commercial facilities, including retail, hotel, hospitality, and office space. The ₹250-crore project, which will be ready by 2024, will be developed by Omaxe Limited, said officials associated with the project.

While DDA manages two other golf courses in the city -- an 18-hole Qutub golf course in Lado Sarai and the nine-hole Bhalaswa golf course -- the upcoming project in Dwarka Sector 24 will also include a club house and driving range, officials said.

As part of its key project aimed at a major infrastructure overhaul in the region, DDA is also constructing its first-ever luxury flats in Dwarka overlooking the golf course that is expected to be opened for draws in the second half of the year.

All sports facilities of DDA can be used by the public through a daily booking, apart from the various memberships that it offers.

The existing sports facilities owned and managed by DDA include 15 sports complexes, three mini sports complexes, two golf courses, 17 swimming pools and 40 multi-gyms.

Conceptualised in the 1980s, the Dwarka sub-city has an estimated population of nearly one million comprising mostly middle and upper middle income groups. There are 352 cooperative group housing societies and 52 pockets developed by DDA, making it one of the biggest residential hubs in the city.

"This is a great facility and residents are eagerly waiting for the sports complexes. However, the population of Dwarka is huge and it is difficult for five such facilities to give membership to everyone. So, they should allow everyone to use the facility, even non-members," said Sanjeev Bhatnagar, president of Shaman Vihar society in Dwarka Sector 23.

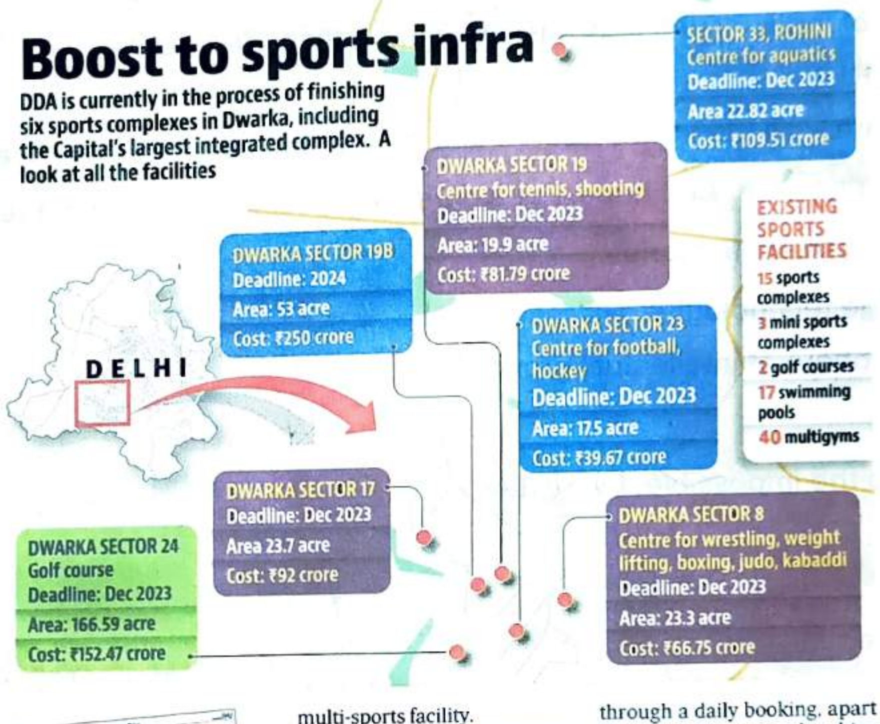

Infra injection key fillip for Dwarka

DEC 22,2022: HT reported the five key projects which will come up in Dwarka, including a 53-acre sports facility featuring a 30,000-seater stadium.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JUNE 11, 2023
NEWSPAPERS- -DATED-

DDA writes to LG over DJB delay on nod for rehab work

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority has written to lieutenant governor VK Saxena and alleged that the work to lay water and sewer lines at Jailorwala Bagh, a rehabilitation housing project for slum dwellers, was stalled due to Delhi Jal Board's delay in giving the necessary approvals.

While the project was ready to be inaugurated and the houses allotted, the absence of water and sewer network had delayed the project, it further alleged.

DDA has also added that the residents of Kalkaji rehabilitation project were forced to rely on tankers for water in absence of a regular water supply by DJB.

While the two in situ slum rehabilitation projects have been executed by DDA, DJB is controlled by the Delhi government. No immediate reaction was available from the AAP government.

According to officials from the LG secretariat, 1,675 multi-storey dwelling units have been built under the in situ rehabilitation of slums at Jailorwala Bagh near north Delhi's Ashok Vihar for which the draw of lots has also taken place.

They added while DDA had already paid Rs 16 crore in February 2023, DJB was yet to provide the approved water supply and sewer network drawings. "The agency cannot lay these services and construct roads over them unless it has the approved drawings from DJB. The work is getting unnecessarily delayed due to this," said an official.

"When the DDA engineers spoke to the DJB officials, they were informed that the 'competent authority' had 'withheld' the release of drawings. The DJB officials said the reasons can be informed only after the minutes of meeting are issued," claimed an official from the LG Secretariat.

While the project was ready to be inaugurated and the houses allotted, the absence of water and sewer network had delayed the project, the letter alleged

According to officials, Saxena had visited the project on April 4 this year and had directed DDA to complete the work latest by May 31. "The project is to be inaugurated by a dignitary this month," said an official.

Referring to the Kalkaji project, officials said despite having the underground water reservoirs and a network of water lines, there was no supply of piped water. Over 1,800 families have shifted to multistorey flats in Kalkaji.

Govt, LG office spar over Yamuna plans

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Water minister Saurabh Bharadwaj challenged lieutenant governor VK Saxena on Saturday to show any new projects or initiatives launched by him to clean the Yamuna. The minister said that Saxena was trying to claim all credit for the Delhi Jal Board's significant progress in cleaning the river.

In response, Raj Niwas termed the statements of the water minister as "petty, self-defeating and laughable" and quoted the order of National Green Tribunal giving Saxena the power to head a high-level committee on the river cleaning.

Bharadwaj's claim was that all progress made in cleaning the Yamuna's water was the result of the comprehensive six-point action plan announced by chief minister Arvind Kejriwal in November 2021. Delhi government strongly criticised what it called the "misleading claims" of the LG's office on the river cleaning efforts.

DJB's six-point action plan had steps like increasing sewage treatment capacity, in-situ treatment of sewage in major drains, upgradation of effluent treatment plants to handle industrial waste, linking of community toilets and JJ clusters to the sewage system, expanding household sewage connections and desilting and rehabilitating the sewerage system. "It is evident that the LG has not sanctioned or approved even a single project related to the Yamuna cleaning. The ongoing attempts to steal credit for the hard work and dedication of Delhi government are unwarranted and unjust," declared Bharadwaj.

Bharadwaj's claim was that all progress made in cleaning the Yamuna's water was the result of the comprehensive six-point action plan announced by CM Arvind Kejriwal

Raj Niwas alleged that in the past eight years, the state government had only made hollow promises and not delivered on the Yamuna cleaning. "Had the government done a single concrete thing with regards to cleaning the Yamuna in the last eight years, apart from making hollow announcements, issuing advertisements and hoisting banners, NGT would not have slammed Delhi government for inaction on this front and constituted a special high-level committee and requested the LG to chair it," a statement released by the LG's office said.

The statement also quoted the observations of NGT, which, in January, said that the "situation to a great extent remains unsatisfactory" with regard to the river. The green court had added, "In the light of above discussion, we constitute a high-level committee of authorities in Delhi where pollution of Yamuna is higher (about 75%), compared with other river basin states. We request the lieutenant governor of Delhi, who is chairman of DDA and administrator of Delhi under Article 239 of the Constitution, to head the committee".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, JUNE 11, 2023

DATED

Credit wars: AAP govt, L-G spar over Yamuna yet again

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 10

THE DELHI government and the L-G Office confronted each other Saturday over credit for a marked improvement in pollution levels of the Yamuna river.

Water Minister Saurabh Bharadwaj issued a challenge to the Delhi L-G to present any new projects he had initiated for the river's cleanliness "claiming credit" for the AAP government's work.

An L-G House official termed the allegations "petty, self-defeating, and laughable". The official claimed that had the Delhi government done a "single concrete thing" with regard to cleaning the Yamuna in the last eight years, apart from making "hollow announcements", the National Green Tribunal would not have "slammed the Delhi government for inaction and constituted a special high-level committee and requested L-G to chair it."

The official quoted from the NGT order dated January 9, in which the bench had observed, "It does appear that the situation to a great extent remains unsatisfactory, in violation of judgment of Hon'ble Supreme Court and orders of this tribunal, fixing rigid timelines, which are being defied at whims, without accountability and without visible improvement..." It further said: "... we constitute high-level committee of concerned authorities... We request Lieutenant Governor, Delhi, who is Chairman DDA and Administrator of Delhi... to head the committee."

Water quality in the Yamuna is showing signs of improvement with the biochemical oxygen demand – proportion of which determines pollution levels in a water body – having fallen compared to last year in Najafgarh drain and in the river from the point where it meets the drain, according to Delhi Pollution Control Committee figures presented at a meeting on Friday.

Saurabh Bharadwaj and the L-G's Office traded barbs over the issue

During the fifth meeting of the high-level committee, chaired by L-G VK Saxena, progress on work was reviewed.

A day later, Bhardwaj accused the L-G of seeking to claim credit for Delhi government's "significant progress" in cleaning the river, stating that progress made had been executed in accordance with six-point action plan announced by the Chief Minister in November 2021. These, he said, included increasing STP treatment capacity, in-situ treatment of major drains, upgradation of CETPs to handle industrial waste, linking community toilets and JJ clusters to the sewage system, expanding household sewage connections, and desilting and rehabilitating the sewerage system.

"Regrettably, the L-G office has been misrepresenting the initiatives undertaken by the Delhi government as his own. The L-G office copies minutes of meetings and presentations from departments such as DJB and Irrigation and Flood Control Department, and presents them falsely claiming that these are the sole achievements of the L-G," Bhardwaj alleged.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 11 जून, 2023 -DATED-

समस्याओं से जूझ रहे कालकाजी एक्सटेंशन इलाके के डीडीए फ्लैटों में रहने वाले लोग

लोगों का आरोप, तीन-तीन दिन बाद आता है पानी, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं

जागरण पड़ताल

कालकाजी एक्सटेंशन स्थित डीडीए फ्लैट्स परिसर में जगह-जगह फैली गंदगी व लीकेज के चलते फैला पानी ● जागरण

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के कालकाजी एक्सटेंशन इलाके में झुग्गीवासियों के लिए डीडीए की ओर से बनाए गए फ्लैटों व डीडीए फ्लैट परिसर में समस्याओं का अंबार है। 'जहां झुग्गी वहीं मकान' के तहत दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गीवासी गंदी बस्तियों से निकल कर साफ-सुथरी जगह और सुंदर फ्लैटों में रहने का सपना लेकर यहां आए थे, लेकिन यहां भी उन्हें गंदगी, कूड़ा व अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

बता दें कि जागरण की टीम ने डीडीए फ्लैट परिसर की पड़ताल की तो परिसर में जगह-जगह मलबे का ढेर, कूड़ा, गंदगी और गंदा पानी फैला दिखा। इन फ्लैटों में रह रहे लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यहां पानी, सफाई व लिफ्ट आदि कई समस्याएं हैं।

कालकाजी एक्सटेंशन के डीडीए फ्लैट परिसर में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि यहां केवल खारा पानी ही मिलता है, उसमें भी समस्या झेलनी पड़ती है। दो-दो तीन-तीन दिन पर पानी मिलता है, वह भी काफी कम मात्रा में मिलता है। इन फ्लैटों में रह रहे लोगों का कहना है कि फ्लैट मिलने के पांच साल के अंदर तक सभी तरह की मेंटेनेंस इत्यादि की जिम्मेदारी डीडीए की है, लेकिन परिसर में मौजूद डीडीए अधिकारी किसी भी समस्या की सुनवाई बामुश्किल ही करते हैं। परिसर में कई पाइपें टूटी हुई हैं। अनावश्यक रूप से पानी गिरने से सीलन घरों तक पहुंच जाती है। इससे काफी समस्या होती है। परिसर के सी-ब्लाक में रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि 14 तल की इमारत में यहां लिफ्ट संबंधी कई समस्याएं हैं।

इस ब्लाक में लिफ्ट कई तलों पर कमांड दिए जाने के बाद भी नहीं रुकती हैं और इमारत में लिफ्ट लगी होने के बावजूद उन्हें सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार इन लिफ्टों में उनके बच्चे व घर के अन्य सदस्य फंस भी चुके हैं। इसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें इस लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका।

कई बार तीन-तीन दिन तक हमारे घरों में पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। संबंधित कर्मचारी से बोलने पर वे तरह-तरह के बहाने करते हैं। काफी कम पानी की आपूर्ति की जाती है। पांच साल तक मेंटेनेंस का काम देखने की जिम्मेदारी डीडीए की है। - **मोनिका राय**

सी-ब्लाक में अंदर से कमांड देने पर लिफ्ट काम करती है, लेकिन 11वें और 14वें तल से यदि कोई बाहर से लिफ्ट को रुकने का कमांड देता है तो लिफ्ट इन तलों पर नहीं रुकती है। - **पंकज**

मेरी बेटी शनिवार को लिफ्ट में आठवें तल पर आधे घंटे तक फंसी रही। कड़ी मशक्कत के बाद बेटी को बाहर निकाला जा सका। - **सुनील**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
NAME OF NEWSPAPER: THE SUNDAY EXPRESS, JUNE 11, 2023 TED

MUSEUM, HOUSED IN SIRI FORT AREA, REOPENS AFTER TWO YEARS

Officers' club to heritage space: Inception of ASI Children's Museum

VANDANA KALRA
NEW DELHI, JUNE 10

IN THE heart of Delhi, in the bustling neighbourhood of Siri Fort, a rather nondescript board welcomes visitors to the ASI Children's Museum. Shut for over two years, its doors opened again late last month and initiatives are now being planned to invite children and introduce them to sculptures from prominent historical sites located across India whose replicas the museum houses.

"No one can possibly visit all these sites that are such significant parts of our history," says author Ajeet Cour, who was involved in the planning of the museum almost two decades ago. She vividly recalls how in the late '90s, she found labourers digging a mound near the Siri Fort wall one day. "At first, I thought they were working for the ASI. But on questioning them, I realised they were from the DDA. This (the digging) was within 100 metres of a protected monument. I immediately took up the matter with the ASI, but it took over six months for the digging to stop," says Cour.

Though a DDA Officers' Club was subsequently built in the premises, a persistent Cour took the matter to former Prime Minister VP Singh who, she says, decided to pursue it through a court case, and finally ASI got charge of the space.

The then Culture Minister Ambika Soni decided to turn the building into a heritage museum for children. The conceptual plans were prepared and, in consultation with the National Museum and archeologist KK Muhammed, sculptures from around India and belonging to different time periods were shortlisted to be created as reproductions to introduce children to India's rich heritage.

"It's a treasure trove for children," says Cour, recalling how her daughter Arpana Caur commissioned her friends in Garhi to make two of the sculptures — Chola Natraj and Nandi Bull.

The museum houses replicas of sculptures from prominent historical sites located across India. *Abhinav Saha*

Meanwhile, under the aegis of the ASI, artists were allotted a temporary space in Old Fort to work on reproductions.

When the museum opened in 2007, on view were around 30 sculptures, each accompanied by an elaborate text that not just mentions its location and period but also describes its significance and associated legends.

A plaque that gives details of a Standing Buddha sculpture from the 5th Century in Mathura shares that this is a rare sculpture of Buddha in Abhaya mudra (with the right hand raised and palm facing outwards). The Shalabhanjika sculpture, dated 9th-10th Century, from the Pratihara period and located in Gyaraspur in Madhya Pradesh, carved in buff sandstone and in dvibhanga mudra, is introduced to children as Indian Mona Lisa. "Is not her smile more enchanting and mystique than even Mona Lisa?" questions the plaque.

Aparna also reveals that an arch from the Khilji period was also discovered on-site a few weeks back when the construction for a new gate was going on.

Sharing that footfall has been encouraging since the museum opened, Praveen Singh, superintending archaeologist, Delhi circle, ASI, who is currently handling operations at the museum, shares that more sculptures will soon be added. "There is a proposal to make more replicas. We also intend to create models in the outdoor area and have an audio-video hall," he says.

Before children leave the premises, meanwhile, lessons are also imparted on the need to appreciate and protect historical monuments through a showcase that introduces them to such sites across Delhi and documents how they are often vandalised. "It is important to educate children and teach them to value our past," says Cour.

नई दिल्ली, 11 जून, 2023 दैनिक जागरण 7

विभाजन के भरे जख्म, खड़ी कीं विकास की इमारतें

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

एक ओर भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं इसी के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) भी 75 साल का हो गया है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि डीडीए ने केवल दिल्ली में विकास की इमारतें ही खड़ी नहीं कीं, बल्कि देश की आजादी के बाद विभाजन ने जो जख्म दिए थे, उन्हें भी भरा है।

विकास सदन •

- दुनिया के प्रमुख शहरों के साथ कदमताल कर रहा दिल्ली का आवासीय ढांचा
- डीडीए ने राजधानी को रहने योग्य बनाया
- अब तक 54 हाउसिंग योजनाएं ला चुका है डीडीए

डीडीए ने अभी तक दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया ही है, आने वाले समय में भी इसे बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मास्टर प्लान-2041, यमुना डूब क्षेत्र का विकास, इन सीटू डेवलपमेंट, विरासत संरक्षण और ट्रांजिट ओरिएंटिड परियोजनाएं राजधानी का नक्शा बदल देंगी।

-सुभाशीष पांडा, उपाध्यक्ष, डीडीए

वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता व विभाजन ने दिल्ली की आबादी को सात लाख से बढ़ाकर वर्ष 1951 तक 17 लाख कर दिया था। सभी खुली जगहों पर शरणार्थियों का कब्जा था। नागरिक सेवाएं लगभग ध्वस्त हो गई थीं। उस समय के दो स्थानीय निकाय- दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और नगर निकाय, बदलते परिदृश्य से निपटने के लिए सक्षम नहीं थे। ऐसे में दिल्ली के लिए योजना बनाने और इसके तीव्र बेतरतीब विकास की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने समिति बनाई, जिसने सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एकल योजना व नियंत्रण प्राधिकरण की सिफारिश की। **नतीजा**, दिल्ली (भवन संचालन नियंत्रण) अध्यादेश-1955 को अधिसूचित कर एक योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का गठन किया गया था।

डीडीए की ओर से आवासीय परियोजनाओं का विकास वर्ष 1967 में घरों के निर्माण और बिजली, जलापूर्ति, सीवेज निपटान के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ शुरू हुआ।

डीडीए अपनी स्थापना से अब तक 54 हाउसिंग योजनाएं ला चुका है। इनमें विभिन्न श्रेणियों के 4,17,063 फ्लैट शामिल हैं जिनमें 86,764 जनता फ्लैट, 1,17,858 एलआइजी फ्लैट, 60,673 एमआइजी फ्लैट, 3,715 एचआइजी फ्लैट, 1,154 ईडब्ल्यूएस फ्लैट, 24,045 ईएचएस फ्लैट और 70,054 एसएफएस फ्लैट हैं। इसके अलावा 888 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में 1,14,135 फ्लैट बनाए हैं, जिनमें फ्री होल्ड कन्वर्संस वाले 80,336 फ्लैट हैं। वहीं, 33,799 फ्लैट लंबित हैं। साथ ही 118 को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी बनाई हैं। इनमें 31,201 प्लाट, 34,253 फ्री होल्ड और 3948 लीजहोल्ड संपत्तियां शामिल हैं।

वहीं, वर्तमान विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में एसएफएस, एमआइजी, एलआइजी, जनता फ्लैट का निर्माण शामिल हैं, जिनके मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही डीडीए स्थानीय बाजारों में खुदरा दुकानों, शापिंग काम्प्लेक्स, कार्यालय परिसरों, अस्थायी औद्योगिक सेट अप, अस्पतालों, सामुदायिक हाल, क्लब, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक अलगाव केंद्रों आदि जैसी वाणिज्यिक संपत्तियों का निर्माण, विकास व रखरखाव भी करता है। इन संपत्तियों का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: Hindustan Times
NEW DELHI
MONDAY
JUNE 12, 2023

DDA to ready 17,800 flats in a yr

Snehil Sinha
snehil.sinha@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) is set to launch schemes to allot 17,829 flats in various categories in two phases over the next year, according to Subhasish Panda, vice-chairperson, DDA.

Officials said that 11,449 flats will be ready by the end of October this year while another 6,380 flats will be ready by March 2024. These include flats in the high income group (HIG), mid income group (MIG), low income group (LIG) as well as economically weaker sections (EWS) categories. The largest number of flats will be in the MIG category, said Panda.

"We are on the verge of completing most of these flats which will be ready in two batches — by the end of October this year and the end of March next year," added Panda.

All of the upcoming DDA flats will be in Dwarka Sector 19B, Bhakarwala near Mundka, Dwarka Sector 14, and Narela sectors A1 to A4. Officials added that the HIG or luxury flats are coming up in Dwarka's Sector 19B and are a new category for DDA as well. In the Dwarka flats, DDA will offer luxury flats with penthouses and terrace gardens overlooking a golf course for the first time. The society in Sector 19B will have 116 HIG flats and 14 penthouses, along with 328 EWS units. Apart from Dwarka, some of the HIG flats will also be Narela.

Officials said that the price for these flats has not been finalised yet. However, the authority may be inviting applications for the draw of lots around Diwali this year, and the allotment is expected by early next year.

"The size of the penthouses will be 266 square metres (sqm) and the HIG flats will come in two sizes of 129 sqm and 150 sqm. Meanwhile, the MIG flats will be of 84 sqm and the LIG flats will be 40 sqm," said a DDA official.

The flats expected to be ready by October include 2,938 HIGs, 2,491 MIGs, 316 LIGs, and 3,904 EWS category flats. Additionally, by March 2024, 1,125 HIGs, 3,396 MIGs, and 1,859 EWS units will also be ready, officials added.

DDA, till date, has launched 54 housing schemes, which include 888 group housing societies and 118 cooperative housing societies, with a total of 417,063 flats in all categories.

All of the upcoming DDA flats will be in Dwarka Sector 19B, Bhakarwala near Mundka, Dwarka Sector 14, and Narela sectors A1 to A4.
HT ARCHIVE

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, JUNE 12, 2023

NAME OF NEWSPAPERS--DATED-------------

Cycle Walk: DDA Plan Ready For 15km Track Amid Greens, Bridges

Leg A Route To Pass Through GK II, Saket, Chirag Dilli; Project To Cover 200km

Vibha.Sharma@timesgroup.com

GOING GREEN

DDA'S DELHI CYCLE WALK PROJECT

- To develop about **200 km of dedicated 'cycle walk track'** for pollution-free commuting
- Route divided into **5 phases**, covering Tuglaqabad, North Campus, Janakpuri, among other areas

COST OF PROJECT | **₹550 crore** (80% under Urban Development Fund, 20% by DDA)

- The track will pass through green areas of the city or will be elevated

PHASE-I | Work in progress

Covers	Cost	Deadline
36 km	**₹50 crore**	**2025-end**

Divided into three legs | Neelgai Line (Leg A), Peacock Line (Leg B) and Bulbul Line (Leg C)

- A detailed report submitted to SC-appointed Central Empowered Committee; survey pending
- Ridge Management Board has given recommendations

Leg A will cover Tughlaqabad, GK II, Govindpuri, Malviya Nagar, Saket District Court, Chirag Dilli, Masjid Moth and neighbouring areas

Leg B will cover Lado Saria, Vasant Kunj Mall, etc

Leg C will cover GK-I ,Sant Nagar, Nehru Place, Asiad Village, Siri Fort, etc

FEATURES

- 2.5m-wide cycle track + 2m-wide pedestrian track
- Plazas
- Intermediate stations
- Land bridges
- Other ancillary development work

PHASE-1 TRACK

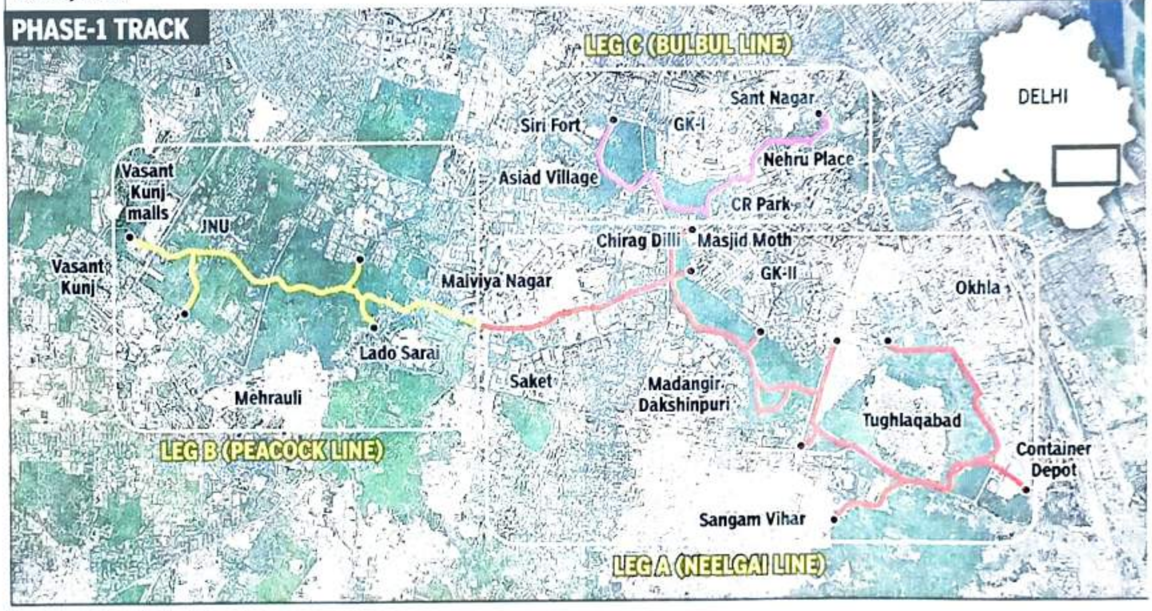

New Delhi: The Delhi Development Authority's (DDA) Delhi Cycle Walk has seen development recently with the authority submitting a plan for Phase I (Leg A) to the Supreme Court-constituted Central empowered Committee (CEC) and Ridge Management Board (RMB) for necessary approvals.

The project is unique because it aims to provide cycling tracks along the greens of the city and elevated bridges to allow hindrance-free movement. "The project aims to promote pollution-free green commuting and won't be connected to roads," an official said.

"While the whole project will cover 200 km and be developed in five phases, we are at present focusing on 36 km long Phase I, having both on-grade (surface) and elevated tracks," said DDA vice-chairman Subhasish Panda.

Phase I is divided into three legs – Neelgai Line (Leg A), Peacock Line (Leg B) and Bulbul Line (Leg C). While Leg A will cover Tuglakabad, GK II, Govindpuri, Malviya Nagar, Saket District Court, Chirag Dilli, Masjid Moth and neighbouring areas, Leg B will cover Lado Saria, Vasant Kunj Mall, etc. and Leg C will cover GK I, Sant Nagar, Nehru Place, Asiad Village and the Siri Fort area. The route will connect some Metro stations too.

At present, DDA's focus is Leg A, which is 15.5km long and a detailed report on this is submitted to CEC. "They will need to visit the site and do a survey. Based on their recommendations and suggestions, further changes would be made in the project. Considering the cycle route will be passing through forest, parks (including Archaeological Survey of India sites) and private campuses, we have also obtained approvals from the RMB as well as National Monument Authority (NMA). As soon as the nod from the CEC is received, we will apply for related permissions from other agencies," said the DDA official.

The Leg A project will mostly have surface track and the project will cost Rs 50 crore. "Though we have set targets for implementing the project, delays happen in getting approvals and necessary sanctions. We are still committed to complete this portion in a time bound manner," said the official.

Officials said that 80% of the cost of the project will be borne by the urban development fund of MoHUA and the rest by DDA.

The plan includes 2.5-metre-wide cycle tracks and two-metre-wide pedestrian tracks. The tracks will have origin and destination plazas, intermediate stations, land bridges and other ancillary development work. "Considering the route will pass through the city's green area mainly, a kuccha track will be preferred. The cycling will give people an opportunity to enjoy the greenery which will be developed accordingly," said the official.

The remaining four phases of the project include the 65-km phase 2 covering Vasant Kunj (Block C), Moti Bagh, South Campus, Dhaula Kuan, Talkatora Stadium, Rajendra Nagar, Rajendra Place, Pusa agriculture institute, Janak Puri, Dilli Haat, Mayapuri Metro etc.

Phase 3 will be 46-km-long and will cover north Delhi. Phase 4 will be 25-km-long and cover south east areas such as Nizamuddin, Batla House, Okhla, Jasola, and Mohan Estate. Phase 5 will be 29 km long covering Chattarpur, Maidan Garhi, Deoli and other areas.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली, 12 जून, 2023 दैनिक जागरण III

साढ़े तीन साल में साढ़े 18 हजार को ही मालिकाना हक

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

वर्ष 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राजधानी की 1731 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को संपत्ति का मालिकाना हक देने की स्कीम शुरू की थी, लेकिन अभी तक यह स्कीम अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी है। आलम यह है कि करीब साढ़े तीन वर्ष की अवधि में लगभग साढ़े 18 हजार लोगों को ही कन्वेयेंस डीड (सीडी) जारी की जा सकी है। आम जन को जहां डीडीए के अधिकारियों से शिकायत है, वहीं डीडीए का कहना है कि प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोशिश चल रही है।

फरवरी 2020 के विधानसभा चुनाव से पूर्व 29 अक्टूबर 2019 को इस महत्वाकांक्षी स्कीम की शुरुआत केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के हाथों की गई थी। कहा गया था कि इससे अनधिकृत कालोनियों में न केवल बेहतर ढंग से विकास हो सकेगा बल्कि यहां रहने वालों को बैंक से ऋण भी मिल पाएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने स्कीम पर सवाल उठाए, लेकिन लोगों ने फिर भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। विचारणीय पहलू यह कि इन कालोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं।

इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले लोगों का कहना है कि मालिकाना हक पाने की प्रक्रिया सहज नहीं है। लोग कोशिश करते भी हैं तो अधिकारी गंभीरता से अपना काम नहीं करते। इसी का नतीजा है कि आवेदन अस्वीकृत हो जाते हैं। डीडीए के सूत्र बताते हैं कि पीएम उदय योजना में मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में ज्यादातर वो अधिकारी तैनात रहे हैं जो डीडीए में दो तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए होते हैं। चूंकि इनकी जवाबदेही बहुत नहीं रहती तो अपेक्षित परिणाम भी नहीं आ पाते।

किराडी की अनधिकृत कालोनी में बने मकान • जागरण आर्काइव

1731 अनधिकृत कालोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने की स्कीम

• कठिन प्रक्रिया के चलते फरवरी 2020 में शुरू की गई मुहिम नहीं पकड़ पा रही है रफ्तार

पीएम उदय स्कीम का ब्योरा (31 मई 2023 तक)	
कुल पंजीकरण	4,62,330
आवेदन आए	1,13,518
आवेदनों पर कार्रवाई	1,13,254
कन्वेयेंस डीड जारी हुई	18,568
अस्वीकृत आवेदन	29,895
लंबित आवेदन	65,055
आवेदक के स्तर पर लंबित मामले	62,206
डीडीए के स्तर पर लंबित मामले	2,849
डीडीए द्वारा अभी तक लगाए गए विशेष शिविर	736
विशेष शिविरों में हुए पंजीकरण की संख्या	2,732

हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर पात्र को मालिकाना हक मिले। फिर भी कुछ मामलों में दस्तावेज पूरे न होने से दिक्कत आ जाती है। अब हम इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
-सुभाशीष पांडा, उपाध्यक्ष, डीडीए

दो बार पूरी की प्रक्रिया, फिर भी हाथ खाली

2019 से अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रयास कर रही हैं बुजुर्ग दर्शन

बवाना निवासी दर्शन दिसंबर 2019 से अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रयास कर रही हैं। आठ दिसंबर 2019 को पहली बार पंजीकरण कराया। डीडीए से नंबर-08122019043637/163 मिला। इस नंबर के तहत 950 रुपये की फीस देकर जीआइएस सर्वे कराया। उसके बाद कभी कोई कागजात मांगे गए तो कभी कोई शपथ पत्र। आखिर में जून 2021 में आवेदन रद कर दिया गया। आठ जुलाई 2021 को नए सिरे से पंजीकरण कराया और नंबर-08072021104034/428068 मिला। हजार रुपये खर्च कर जीआइएस सर्वे भी दोबारा करवाया। डीडीए ने 11 हजार फीस लेकर ग्रीनशीट दे दी और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने को कहा। 20 से 25 हजार रुपये खर्च करने के बाद नौ नवंबर 2021 को रजिस्ट्री मिल गई। लेकिन अभी मार्च 2023 में डीडीए से कारण बताओ नोटिस मिला और रजिस्ट्री रद कर दी गई। कहा गया कि प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होगी।

अपनी संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े कागजात दिखाती बवाना निवासी दर्शन • जागरण

फतेहपुर बेरी गांव के गंदे पार्क और तालाब के सुंदरीकरण कार्य का हुआ शुभारंभ

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से रविवार को छतरपुर इलाके के फतेहपुर बेरी गांव में गंदे पड़े पार्क और तालाब के सुंदरीकरण के कार्य का शुभारंभ किया गया। पार्क का शिलान्यास डीडीए के चीफ इंजीनियर कमल सिंह मीणा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माधुरी प्रसाद की उपस्थिति में सांसद प्रतिनिधि हिमांशु बिधूड़ी, समाजसेवी ऋषिपाल और फतेहपुर बेरीगांव के लोगों की ओर से संयुक्त रूप से किया गया।

समाजसेवी ऋषिपाल महाशय ने बताया कि साल 2019 से ग्रामवासियों के सहयोग से गंदे पार्क और तालाब के सुंदरीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में 2019 में ही स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी को इलाके में जीर्ण-शीर्ण हालत में मौजूद ऐतिहासिक तालाब के सुंदरीकरण की अपील की थी। अब उनकी और ग्रामवासियों की मेहनत रंग लाई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 मार्च 2021 को इस गांव को शहरीकृत गांव के रूप में मान्यता दे दी और यह पूरा इलाका डीडीए के अधीन हो गया। इससे पहले यह दिल्ली सरकार के अधीन था। तभी 24 नवंबर 2021 को डीएम दक्षिणी जिला, डीडीए के अधिकारी और सांसद रमेश बिधूड़ी ने ऋषिपाल की अगुवाई में बुलाई एक बैठक में यह तय किया कि जल्द इस गंदे तालाब का सुंदरीकरण किया जाएगा।

ग्रामवासियों की सहूलियत के लिए अब इस तालाब पर लाइटें लगाई जाएंगी और वाकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। तालाब के आसपास बैठने के लिए बेंच और पौधे लगाए जाएंगे।

फतेहपुर बेरी गांव में गंदे पड़े पार्क व तालाब के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास करते डीडीए के मुख्य अभियंता कमल सिंह मीणा (दाएं से दूसरे), सांसद प्रतिनिधि हिमांशु बिधूड़ी (नीली शर्ट में), ऋषिपाल (बाएं से तीसरे) व ग्रामवासी • सौ. आयोजक